

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 253-253

दिनांक:- 08-08-2018-09/8/2018

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री आदर्श शास्त्री

क्या उपमुख्यमंत्री/ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क संख्या	प्रश्न	उत्तर																											
क	दिल्ली में कार्यरत को-ओपरेटिव सोसायटीज की संख्या, इनसे लाभान्वित हो रहे लोगों की संख्या क्या है;	दिल्ली में कार्यरत को-ओपरेटिव सोसायटीज की संख्या 5803 है इनसे लाभान्वित हो रहे लोगों की संख्या आर० सी० एस कार्यालय में संकलित नहीं है																											
ख	और इन सोसायटीज के निर्माण के क्या मानक है;	<p>इन सोसायटीज के निर्माण के मानक निम्न है</p> <p>अनुसूची -VI की धारा (I) के उप-नियम - 1 नियम 5 के अनुसार सोसायटीयो का पंजीकरण कार्यालय सहायकी समितियों द्वारा किया जाता है। सहायक रजिस्ट्रार जांच करेंगे कि क्या प्रमोटर वास्तविक हैं और अलग-अलग परिवार से हैं और उस क्षेत्र में उसी प्रकार का कोई अन्य सोसायटी नहीं है और इसमें सफलता की पूरी संभावना है। रजिस्ट्रार / सहायक रजिस्ट्रार प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और मुख्य प्रवर्तक को सूचित करते हैं जो अपने साथी प्रमोटरों को मंजूरी और शेयर साझा करने के बारे में सूचित करेगा, प्रवेश शुल्क मुख्य प्रमोटर द्वारा एकत्र किया जाएगा जो दिल्ली राज्य को-ओपरेटिव बैंक में सस्पेंस खाते में प्रस्तावित सोसायटी के नाम पर बैंक की नजदीकी शाखा में जमा किया जाएगा।</p> <p>इस राशि को इकट्ठा करने के बाद, मुख्य प्रमोटर पंजीकरण प्रस्ताव की मंजूरी और प्रबंधन का चयन करने के लिए प्रमोटरों की जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित करेगा। इस बैठक में प्रमोटर सहायकी समिति के गठन के लिए एक प्रस्ताव अपनाएंगे और नए निर्वाचित सचिव और प्रधान को रजिस्ट्रार को पेपर जमा करने और इस तरफ बाई-लाज में हस्ताक्षर, कटौती या परिवर्तन करने के लिए अधिकृत करेंगे।</p>																											
		<table border="1"><thead><tr><th>S. NO</th><th>Class</th><th>Minimum No. of Members</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>शहरी बैंक</td><td>3000</td></tr><tr><td>2</td><td>शहरी क्रेडिट सोसायटी</td><td>50</td></tr><tr><td>3</td><td>उपभोक्ता स्टोर</td><td>100</td></tr><tr><td>4</td><td>ओद्योगिक (प्रो) सहायकी समिति</td><td>15</td></tr><tr><td>5</td><td>ओद्योगिक (सेवा) सहायकी समिति</td><td>15</td></tr><tr><td>6</td><td>समूह आवास समिति</td><td>60</td></tr><tr><td>7</td><td>कृषि सेवा / क्रेडिट समिति</td><td>50</td></tr><tr><td>8</td><td>डेयरी/ मुर्गी पालन समिति</td><td>15</td></tr></tbody></table>	S. NO	Class	Minimum No. of Members	1	शहरी बैंक	3000	2	शहरी क्रेडिट सोसायटी	50	3	उपभोक्ता स्टोर	100	4	ओद्योगिक (प्रो) सहायकी समिति	15	5	ओद्योगिक (सेवा) सहायकी समिति	15	6	समूह आवास समिति	60	7	कृषि सेवा / क्रेडिट समिति	50	8	डेयरी/ मुर्गी पालन समिति	15
S. NO	Class	Minimum No. of Members																											
1	शहरी बैंक	3000																											
2	शहरी क्रेडिट सोसायटी	50																											
3	उपभोक्ता स्टोर	100																											
4	ओद्योगिक (प्रो) सहायकी समिति	15																											
5	ओद्योगिक (सेवा) सहायकी समिति	15																											
6	समूह आवास समिति	60																											
7	कृषि सेवा / क्रेडिट समिति	50																											
8	डेयरी/ मुर्गी पालन समिति	15																											

		9	परिवहन समिति	15
		10	श्रम समिति	15
		11	सुरक्षा सेवा समिति	15
		12	एकीकृत विकास समिति	15
		13	बहुउद्देशीय समिति	30
ग	कोऑपरेटिव सोसायटीज की स्थापना में सरकार की तरफ से क्या सहयोग किया जाता है:	कोऑपरेटिव सोसायटी का पंजीकरण Rule 5 of DCS Rules 2007 के तहत किया जाता है।		
घ	महिलाओं और एस.सी/ एस.टी. समूह के लिए इन कोऑपरेटिव सोसायटीज से किस प्रकार सहयोग किया जाता है:	DCS ACT 2003 & DCS Rule 2007 में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।		
ङ	पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार कि कितनी कोऑपरेटिव सोसायटीज का निर्माण किया गया;	उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं है।		
च	इनसे किसको लाभ पहुंचाया जा सका;	उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं है।		
छ	द्वारका विधानसभा के अंतर्गत कितनी कोऑपरेटिव सोसायटीज काम कर रही हैं; इनका विस्तृत विवरण दे;	द्वारका विधानसभा के अंतर्गत 23 कोऑपरेटिव सोसायटीज आर0 सी0 एस कार्यालय में पंजीकृत हैं। इसमें से 14 शहरी क्रेडिट सोसायटी और 02 समूह आवास समिति द्वारका विधानसभा में पंजीकृत हैं। 07 समूह आवास समिति का कार्यालय आर0 सी0 एस0 आफिस में द्वारका विधानसभा के अंतर्गत पंजीकृत है, परन्तु इनको जमीन का आंबटन द्वारका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुआ है।		
ज	बीपीएल आबादी को इन कोऑपरेटिव सोसायटीज के माध्यम से किस प्रकार लाभ पहुंचाया जा सकता है और	DCS ACT 2003 & DCS Rule 2007 में बीपीएल आबादी को इन कोऑपरेटिव सोसायटीज के द्वारा लाभ पहुंचाने का कोई प्रावधान नहीं है।		
झ	इसके लिए आगे की कोई विशेष योजना हो, तो उसका विवरण क्या है?	उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं है।		

Tanuj
(तनुज भनोट)
सहायक पंजीयक

Assistant Registrar
Registrar Co-operative Societies
Parliament Street, New Delhi